देश के दिल भोपाल में 'मेट्रो' से सफर होगा सुगम

मेट्रो एक नजर

- विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है मेट्रो
- आठ स्टेशनों पर चलेगी मेट्रो, सात किमी की दूरी होगी तय
- महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण में यात्रा का अवसर
- एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगी मेट्रो की बोगी

भोपाल, 19 दिसंबर. राजधानी आज से 'मेट्रो सिटी' बन जाएगी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके बाद वे मेट्रो की सवारी भी करेंगे. वहीं रविवार सुबह 9 बजे से आम लोग भी मेट्रो की सवारी कर सकेंगे.

मेट्रो के स्वागत के लिए राजधानी को संजाने-संवारने का काम शुक्रवार को जारी रहा. सड़कों पर डामरीकरण के साथ डिवाइडरों पर रंग रोगन किया गया. इसी के साथ मेट्रो स्टेशनों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया. भोपाल मेट्रो के पहले चरण में ऑरेंज लाइन 'प्रायोरिटी कॉरिडोर' का शुभारंभ किया जा रहा है. लगभग 7 किलोमीटर के इस खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं.

यह स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय एवं सुभाष नगर है. यह कॉरिडोर शहर के व्यस्त मार्गों पर सुगम यातायात उपलब्ध करेगा और प्रदूषण को कम करने में सहायता प्रदान करेगा. मेट्रो का यह कॉरिडोर नागरिकों की यात्रा को सरल और आसान बनाएगा. भोपाल मेट्रो की अनुमानित लागत 10 हजार 33 करोड़ रुपये है. इसमें प्रायोरिटी कॉरीडोर की लागत 2 हजार 225 करोड़ रुपये है. प्रायोरिटी कॉरीडोर की लंबाई 7 किलोमीटर है और इस कॉरीडोर में प्रतिदिन 3 हजार लोगों के यात्रा करने का अनुमान है.

एम्स से सुभाष नगर एवं सुभाष नगर से एम्स - मेट्रो सेवा समय-सारिणी

एम्स मेट्रो स्टेशन से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन

AIIMS	ALKR	DRMO	RKPS	MPNR	BOC	KVDY	SBNG
09:00	09:03	09:07	09:11	09:14	09:18	09:22	09:25
10:15	10:18	10:22	10:26	10:29	10:33	10:37	10:40
11:30	11:33	11:37	11:41	11:44	11:48	11:52	11:55
12:45	12:48	12:52	12:56	12:59	13:03	13:07	13:10
14:00	14:03	14:07	14:11	14:14	14:18	14:22	14:25
15:15	15:18	15:22	15:26	15:29	15:33	15:37	15:40
16:30	16:33	16:37	16:41	16:44	16:48	16:52	16:55
17:45	17:48	17:52	17:56	17:59	18:03	18:07	18:10
19:00	19:03	19:07	19:11	19:14	19:18	19:22	19:25

सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन

SBNG	KVDY	BOC	MPNR	RKPS	DRMO	ALKR	AIIMS
09:40	09:43	09:47	09:51	09:54	09:58	10:02	10:05
10:55	10:58	11:02	11:06	11:09	11:13	11:17	11:20
12:10	12:13	12:17	12:21	12:24	12:28	12:32	12:35
13:25	13:28	13:32	13:36	13:39	13:43	13:47	13:50
14:40	14:43	14:47	14:51	14:54	14:58	15:02	15:05
15:55	15:58	16:02	16:06	16:09	16:13	16:17	16:20
17:10	17:13	17:17	17:21	17:24	17:28	17:32	17:35
18:25	18:28	18:32	18:36	18:39	18:43	18:47	18:50

कार्यक्रम के मद्देनजर मार्ग रहेगा परिवर्तित

मेट्रो के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान शाम 5 बजे केपहले से से यातायात व्यवस्था परिवर्तित रहेगी. जिंसी चैराहा से सुभाष नगर ब्रिज प्रारंभ तक परिवर्तित मार्ग रहेगायह वाहन एसबीआई तिराहा से जेल मुख्यालय, कंट्रोल रूम होकर एवं सुभाष ब्रिज से प्रभात होकर आवागमन कर सकेंगे. वहीं दो-पहिया एवं चार-पहिया (जीप/कार) सुभाष नगर ब्रिज से प्रभात, बोगदा पुल होकर आवागमन कर सकेंगे. जनता से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन कर यातायात व्यवस्था में सहयोग करें.

कांग्रेस ने मीडिया रणनीति पर की समीक्षा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 19 दिसंबर. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ताओं की एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें संगठनात्मक सुदृढ़ता और मीडिया रणनीति को और प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया.

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तथा मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक उपस्थित रहे. बैठक के दौरान प्रवक्ताओं को सौंपे गए दायित्वों, मीडिया में पार्टी की उपस्थिति, जनहित के मुद्दों पर की गई गतिविधियों तथा अब तक किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई. प्रवक्ताओं के कार्य प्रदर्शन, मीडिया संवाद की प्रभावशीलता और संगठनात्मक समन्वय पर बिंदुवार चर्चा हुई.

बैठक को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में प्रवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने निर्देश दिए कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, विफलताओं और जनता से जुड़े मुद्दों को तथ्यों के साथ जिम्मेदारीपूर्वक समाज और मीडिया के समक्ष रखा जाए.

साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों, आंदोलनों और जनसंघर्षों का प्रभावी प्रचार सुनिश्चित किया जाए. मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मीडिया के साथ निरंतर, समन्वित और सकारात्मक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया.

थाने में घुसकर चाचा और नाबालिग भतीजे को पीटा

भोपाल. एक थाने के भीतर हुई मारपीट की घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शाहजहांनाबाद थाना परिसर में नाबालिग और उसके चाचा के साथ पुलिस के सामने हुई बेरहमी से पिटाई ने सनसनी फैला दी है. जिस थाने में फरियादी न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचा था, वहीं दबंगों ने खुलेआम कानून को चुनौती दी और हिंसा को अंजाम दिया. पीड़ित नाबालिग15 वर्ष का है और दसवीं कक्षा में पढ़ता है. वह अपने चाचा के साथ कार डेंटिंग-पेंटिंग का काम सीख रहा है. चार पहिया वाहन में काम कराने के बाद आरोपियों ने तय रकम देने से इनकार कर दिया. इसी कारण विवाद हुआ.

माताओं को चाइल्ड केयर लीव में राहत नहीं

केंद्र में सुविधा लागू, एमपी में अभी भी इंतजार

साक्षी केसरवानी

भोपाल , 19 दिसंबर. मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक केंद्र सरकार के वर्ष 2018 के उस फैसले को अपने सेवा नियमों में शामिल नहीं किया है, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों की माताओं को बच्चे की आयु सीमा से परे चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान किया है.

नियमों में बदलाव न होने के कारण प्रदेश की शासकीय महिला कर्मचारी इस महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित हैं, जिसको लेकर कई शासकीय महिला कर्मचारियों ने सीएम हेल्पलाइन सहित शासन को भी नियमों में सुधार हेतु पत्र लिखा है. बता दें प्रदेश में शासकीय महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के तहत कुल 730 दिन का अवकाश दिए जाने का प्रावधान है. सामान्य बच्चों की माताओं को यह सुविधा, बच्चे की 18 वर्ष की आयु तक मिलती है, जबकि दिव्यांग बच्चों की माताओं को अधिकतम 22 वर्ष की आयु तक ही अवकाश दिया जा रहा है. वर्ष 2018 में भारत सरकार ने संतान पालन अवकाश के नियमों में संशोधन करते हुए दिव्यांग बच्चों की माताओं के लिए आयु सीमा समाप्त कर दी थी. केंद्र सरकार ने यह निर्णय इस आधार पर लिया था कि दिव्यांग बच्चे की देखभाल आजीवन चलने वाली जिम्मेदारी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने अपने सेवा नियमों में यह व्यवस्था लागू भी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक इस दिशा में बदलाव नहीं हुआ है.

इस मामले में हम वित्त वभाग के साथ बातचीत कर केंद्र और राज्य सरकार के प्रावधानों में कतिपय विसंगति को दूर करने का प्रयास करेंगे. हम दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों के हित में उक्त आशय की सिफारिश सोमवार को कर रहे हैं.
डॉ अजय खेमरिया ,आयुक्त दिव्यांगजन, मप्र शासन

महिला कर्मचारियों का कहना है कि दिव्यांग बच्चे वयस्क होने के बाद भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाते. उन्हें इलाज, पुनर्वास, सुरक्षा और दैनिक जीवन में लगातार सहयोग की आवश्यकता होती है. ऐसे में आयु सीमा तय कर चाइल्ड केयर लीव से वंचित किया जाना व्यावहारिक नहीं है. महिला कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार के फैसले को अपनाते हुए चाइल्ड केयर लीव के नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार इस निर्णय को लागू करती है, तो यह संवेदनशील और सकारात्मक शासन का एक मजबूत उदाहरण होगा.

मानसिक रूप से बीमार युवक ने खुद का गला रेता, मौत

भोपाल, 19 दिसंबर. राजधानी के कमला नगर थाना इलाके में स्थित नेहरू नगर में रहने वाले एक युवक ने सब्जी काटने वाले चाकू से खुद का गला रेत लिया.

घटना गुरुवार रात की है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान हमीदिया अस्पताल में शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सुसाइड के प्रयास के पहले उसने मां से आखिरी बात करते हुए कहा था कि मेरी नासा वाली गर्लफ्रेंड बुला रही है. मैं उसके साथ अंतरिक्ष में जाना चाहता हूं. परिवार वालों ने पुलिस को बताया की मृतक युवक का मानसिक संतुलन खराब था. परिजन उसका कई अलग-अलग मनो चिकित्सकों से उसका इलाज करा चुके हैं, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था. पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है.

सिविल कांट्रेक्टर ने की सुसाइड

भोपाल. अयोध्या नगर थाना इलाके में ऑनलाइन गेम में करीब 30 लाख की रकम हार जाने से तनाव में आए एक सिविल कांट्रेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 30 लाख रुपए उधारी लेने की बात भी लिखी है. मर्ग कायम करते हुए पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है. शारदा नगर निवासी शिवान गुप्ता पिता नरेश गुप्ता सिविल कांट्रक्टर था.

योजना : 1 लाख 93 हजार 329 बकायादारों ने कराया पंजीयन

भोपाल, 19 दिसंबर. विगत 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 का लाभ लाखों बकायादार उपभोक्ता उठा रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 का प्रथम चरण चल रहा है.

इस दौरान अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 1 लाख 93 हजार 329 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 209 करोड़ 47 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 110 करोड़ 09 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है.

मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं, जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया जमा राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं.

ड्रिल के दौरान भीड़ प्रबंधन के सीखे गुर

विशेष संवाददाता

भोपाल. कानून-व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी को मजबूत करने और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल द्वारा 19 दिसंबर को प्रात: 10 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में व्यापक बलवा नियंत्रण ड्रिल का आयोजन किया गया।

यह अभ्यास सेनानी हितेश चौधरी के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुआ, जिसमें वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। ड्रिल के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को भीड़ प्रबंधन, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा बलवा जैसी परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अभ्यास के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिनसे विशेष बलवा नियंत्रण टोलियां और बलवाई दल गठित किए गए।

एमपी पुलिस ध्यान कार्यक्रम करेगी शुरू

विशेष संवाददाता

भोपाल, 19 दिसंबर. विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश पुलिस ने राज्यभर के पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और समग्र कल्याण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार 21 दिसंबर 2025 से प्रदेश के सभी पुलिस थानों में साप्ताहिक ध्यान कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह पहल मध्यप्रदेश पुलिस और हार्टफुलनेस संस्था के बीच 2 फरवरी 2025 को हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत पुलिसकर्मियों को नि:शुल्क ध्यान प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत पुलिस थानों, यातायात इकाइयों, महिला थानों, अनुसूचित जाति/जनजाति इकाइयों और अपराध शाखाओं सहित प्रदेश की 1,000 से अधिक पुलिस इकाइयों में प्रत्येक रविवार नियमित ध्यान सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हार्टफुलनेस प्रशिक्षकों एवं समन्वयकों की उपस्थिति में एक सामूहिक ऑनलाइन ध्यान सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी थानों के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सहभागिता करेंगे। प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि थानास्तर पर समन्वयक निर्धारित किए गए हैं।

सरकार की उपलब्धियां की साझा

भोपाल. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को विभाग की दो वर्ष की उल्ले खनीय उपलब्धियों को मीडिया से साझा किया.

बीएचईएल लेडीज क्लब ने बांटे कंबल और फल

बीएचईएल संवाददाता

भोपाल, 19 दिसंबर. कड़ाके की सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बीएचईएल लेडीज क्लब की अध्यक्ष रोजी उपाध्याय के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट सोसायटी एवं बीएचईएल लेडीज कामगार वेलफेयर सोसायटी द्वारा महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में मानवीय सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर आश्रम में रह रहे 52 आश्रितों को फल एवं कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रोजी उपाध्याय ने कल्याणकारी गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बेसहारा और वंचित वर्ग की सहायता करना एक पुण्य का कार्य है। ऐसे प्रयास न केवल सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि हमें अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से एक समावेशी और सशक्त समाज के निर्माण में सहयोग मिलता है।

उपाध्यक्ष योगिता बघेल ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट का उद्देश्य केवल बेरोजगारों को रोजगारोन्मुख बनाना ही नहीं, बल्कि उन वर्गों की सहायता करना भी है जो दैनिक आवश्यक संसाधनों से वंचित हैं। वहीं उपाध्यक्ष (कामगार) मंजू पटेल ने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है और गरीब व बेसहारा लोग भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। इस अवसर पर दोनों सोसायटियों की कई पदाधिकारी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन खैरुनिशा द्वारा किया गया।

मांग नाबार्ड पेंशन संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन

पेंशन संशोधन में वर्षों से हो रही अनुचित देरी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 19 दिसंबर. नाबार्ड के वरिष्ठ और अति वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने शुक्रवार को पेंशन से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया.

देशभर के 3500 से अधिक सदस्यों वाली ऑल इंडिया नाबार्ड रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पेंशनर्स और अत्यंत वृद्ध परिवार पेंशनर्स इस आंदोलन में शामिल हुए.

पेंशनर्स का कहना है 1 नवंबर 2017 तक सेवानिवृत्त नाबार्ड भर्ती पेंशनर्स की पेंशन संशोधन में वर्षों से अनुचित देरी हो रही है. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परिवार पेंशन संशोधन को भी अब तक लागू नहीं किया गया है. परिवार पेंशन पर निर्धारित अधिकतम सीमा हटाने की मांग भी लंबे समय से लंबित है. आंदोलनरत पेंशनर्स ने बताया कि 20 वर्ष की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन देने और पेंशन का निर्धारण, अंतिम वेतन या पिछले 10 माह के औसत वेतन जो भी लाभकारी हो, के आधार पर करने की मांग पर भी कोई प्रगति नहीं हुई है. जबकि संस्था आरबीआई में ये प्रावधान पहले से लागू हैं. प्रदर्शन में पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि 21 जुलाई 2023 के सरकारी आदेश के कारण नाबार्ड में दो वर्ग के पेंशनर्स बना दिए गए हैं. यह भेदभावपूर्ण है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है. निदेशक मंडल की स्वीकृति के बावजूद तीस माह बाद भी इस भेदभाव को समाप्त नहीं किया गया है. बहुत से 80 वर्ष से अधिक आयु के परिवार पेंशनर्स न्यूनतम जीविका से भी कम पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं. लंबे विलंब के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. इन मांगों के समर्थन में पेंशनर्स ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है. जिसके तहत 5 दिसंबर को मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सामूहिक ज्ञापन सौंपा गया.

नाबार्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी वेलफेयर के अध्यक्ष प्रकाश हतवलने ने बताया यदि इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 5 जनवरी 2026 को मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा.